there was a decline in demand for passenger cars, MUL undertook a series of measures including price re-adjustments to stimulate the demand. Due to this, the fourth quarter has seen a growth of 43% over the third quarter in the sales.

राज्यों के औद्योगिक कार्यकरण की समीक्षा

2985. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राज्यों की औद्योगिक क्षमता और औद्योगिक कार्य-प्रणाली की समीक्षा की है ताकि देश के औद्योगिक विकास के प्रतिशत का आकलन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या आकलन के अनुसार औद्योगिक उत्पादन की प्रतिशतता को निराशाजनक और नकारात्मक पाया गया है;

(ग) उसके कारणों सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक देशभर में सभी राज्यों में फैले हुए औद्योगिक एककों द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणियों के आधार पर तैयार किया जाता है। औद्योगिक विकास का मूल्यांकन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, औद्योगिक विकास अप्रैल-फरवरी, 1997-98 के दौरान 4.9% की तुलना में अप्रैल-फरवरी, 1998-99 के दौरान 3.9% है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार कार्य निष्पादन के एक विश्लेषण से यह पता चलता है कि अप्रैल-फरवरी, 1999 के दौरान कुल 17 द्विअंकीय उद्योग समूहों में से 11 में सकारात्मक विकास दरें प्राप्त हुई हैं जबकि 6 उद्योग समूहों ने नकारात्मक विकास दर्शाया है।

(ग) औद्योगिक विकास में धीमेपन के लिए घरेलू और बाहरी दोनों कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

— घरेलू कारकों में, सामान्य निवेश में कमी के कारण कमजोर मांग शामिल है, जिसका मुख्य कारण पूंजी बाजार में मंदी की स्थितियां थी।

— बाहरी पक्ष की दृष्टि से विश्व निर्यात विकास धीमा रहा है। जिससे भारत के निर्यात विकास पर प्रभाव पड़ा है। चूंकि निर्यात संबंधी उत्पादन औद्योगिक उत्पादन का एक बड़ा भाग होता है इसलिए इससे औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

— पूर्वी एशिया और ब्राजील में मुद्राओं के अवमूल्यन के कारण भारतीय कंपनियां सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा की वजह से भी प्रभावित हुई हैं।

(घ) सरकार ने त्वरित विकास को अधिप्रेरित करने के लिए अनेक उपाय घोषित किये हैं। ये इस प्रकार हैं:—

(1) यू०एस०सी०आर०ए० को रद्द करना और गृह स्वामित्व संबंधी प्रोत्साहन।

(2) सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और पूंजी बाजार को पुनरुज्जीवित करने के लिए शेयरों की पुनः खरीद व अंतःकारपोरेट ऋणों की अनुमति दी है।

1999-2000 के बजट में, तेजी से औद्योगिक विकास करने के लिए उद्योगों के पुनरुज्जीवन हेतु विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। जो इस प्रकार है:—

(1) एकाधिकार तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम को बदलने के लिए नये प्रतियोगी कानून।

(2) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन की सूची को बढ़ाया जायेगा ताकि महत्वपूर्ण उद्योग एवं सेवा क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकें।

(3) उद्योग मंत्रालय के भीतर ही एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण गठित करने की घोषणा की गई है ताकि निवेश अंतः-प्रवाह में तेजी और परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो सके।

(4) उत्पादन शुल्क दर में आमूल-चूल परिवर्तन मौजूदा 11 दरों को घटाकर केवल 3 दरें कर दिया गया है।

(5) 100% मोडवेट ऋण को बनाये रखना।

(6) सीमा शुल्क की मूल्यानुसार 7 प्रमुख दरों को घटाकर 5 मूल दरें की गई हैं।

(7) सड़क निर्माण पर विशेष जोर जिसके लिए डीजल पर एक रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त प्रभार के रूप में वित्त सहायता दी गई है।

(8) लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए ऋण बीमा योजना चलाई जानी है।

(9) गृह निर्माण क्षेत्र के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा की गई है। गृह निर्माण में तेजी से सीमेंट इस्पात और अन्य निर्माण सामग्री की मांग में वृद्धि होगी।

बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने निधियों की ब्याज लागत घटाने के लिए बैंक दर कम कर दी है, "रिपो" दर घटा दी है और सीआरआर कम कर दिया है।

Impact of freight hike on Industrial Units

2986. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether recent hike in freight will affect a large number of Industrial Units and consumable items;

(b) if so, the names of such Industrial Units and consumable items separately;

(c) whether Government propose to provide some relief to consumers in view of unconsiderable hike in freight;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) It is too early to ascertain the impact of the recent freight increase, as it took effect only from 1.4.1999. Whether it will affect the price of the product will depend upon the market conditions. In conditions of over supply, the increase could be partly or fully absorbed by the producers.

(c) to (e) No such proposal is under consideration.

Allocation under PMRY to Maharashtra

2987. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the district-wise grants allocated to Maharashtra under Prime Minister Rozgar Yojana;

(b) whether any special consideration has been given in allotting such grants in Maharashtra to Adivasi areas;

(c) if so, the number of youths benefitted, district-wise in Maharashtra; and

(d) the steps being taken by Government to increase the mobilisation of funds to Maharashtra?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) Under the Prime Minister's Rozgar Yojana, States/UTs are allocated physical targets. The States then allocate district-wise targets. Government of India released funds to States/UTs depending on the achievements of allocated targets only for training purposes and contingencies. The States then incur expenditures for the above purposes.

Subsidy under the scheme is passed on to the Reserve Bank of India for onward disbursement to implementing banks. The statement showing the district-wise allocation of funds under contingencies for the last three years in Maharashtra under the Prime Minister's Rozgar Yojana, as reported by the State Government, is at Statement-I (*See* below). Training funds are not distributed district-wise, but monitored at the State level.

(b) As per report of the State Government, no special consideration has been made while allocating targets/grants to Adivasi areas in Maharashtra.

(c) Details showing district-wise physical targets and progress for the last three years i.e., 1995-96, 1996-97 and